Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

85-2015/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MAY 14, 2015 (VAISAKHA 24, 1937 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 मई, 2015

संख्या 44/1/2015–5 पोल.–चूंकि, हरियाणा सरकार के नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग द्वारा सैक्टर–83, गुड़गांव में कुछ हस्तियों को वाणिज्यिक कालोनियां विकसित करने हेतु लाइसैंस प्रदान करने से सम्बन्धित सार्वजनिक महत्व के सम्बन्ध में गम्भीर मामले और उनमें पाई गई अवैधताएं हरियाणा सरकार के ध्यान में आई हैं;

और चूंकि, राज्य सरकार की राय है कि सार्वजनिक महत्व के सुस्पष्ट मामले, अर्थात् हरियाणा सरकार के नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग द्वारा सैक्टर–83, गुड़गांव में कुछ हस्तियों द्वारा वाणिज्यिक कालोनियां विकसित करने हेतु लाइसैंस प्रदान करने से सम्बन्धित मामलों और उनके पश्चात्वर्ती अंतरण/निपटान/निजी समृद्धि के आरोप, नियमों के अधीन लाभार्थियों की अपात्रता और उससे आनुषंगिक या उससे सम्बन्धित सभी अन्य मामलों में जांच करने के प्रयोजन के लिए जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के न्यायमूर्ति श्री एस. एन. ढींगरा (सेवानिवृत्त) को सन्दर्भ के निम्नलिखित निबंधनों सहित जांच आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं:–

1. आयोग निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में जांच करेगा और अपना निर्णय देगा और सिफारिशें करेगा, अर्थात्;

   (क) परिस्थितियां, जिनके अधीन सैक्टर–83, गुड़गांव में कुछ हस्तियों को वाणिज्यिक कालोनियां विकसित करने हेतु लाइसैंस प्रदान किए गए थे ।

   (ख) क्या उक्त हस्तियां नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा सहित हरियाणा राज्य में विद्यमान लागू विधियों, नियमों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं, मार्गदर्शिकाओं इत्यादि के अनुसार लाइसैंस प्रदान करने के लिए पात्र थीं ?

(ग) क्या कुछ हस्तियां लघु अवधि में मूल लाइसैंसधारी द्वारा लाइसैंस का अंतरण विधियों, नियमों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं और/या मार्गदर्शिकाओं इत्यादि की अतिक्रमणकारी थीं ? और क्या नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की कार्यवाही, विशेष रूप से सरकार को राजस्व की हानि के सन्दर्भ में, जो लाइसैंस देने से पूर्व या बाद में की गई थी, अपेक्षित थी ?

(घ) न्याय के उद्देश्य से अपनाए जाने वाले उपाय (यों) की सिफारिश करना, विशेषतौर पर सार्वजनिक राजकोष के लिए राजस्व की हानि को रोकने की सही कार्यवाही करने के विचार से तथा भविष्य में ऐसे मामलों में सार्वजनिक राजकोष की लागत पर निजी समृद्धि को भी रोकना ;

(ङ) ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना जिसमें विभिन्न वैयक्तिकों, समाचार पत्रिकाओं, राजनैतिक पार्टियों तथा विषय पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्टों इत्यादि द्वारा भी दी गई शिकायतें शामिल हैं ;

(च) न्याय के उद्देश्यों से निष्कर्ष देना तथा सिफारिशें करना विशेषतौर पर आपराधिक षड़यन्त्र आपराधिक दुराचार के आरोप से सम्बन्धित तथा अनुचित निजी समृद्धि, यदि कोई हो, तथा उसमें लोकसेवकों तथा निजी व्यक्तियों की भूमिका; तथा

(छ) सार्वजनिक राजकोष हेतु राजस्व की हानि तथा भविष्य में अनुचित निजी समृद्धि को रोकने के विचार के दृष्टिगत सुव्यवस्थित सुधार के लिए प्रतिकारी उपायों की सिफारिश करना ;

2. आयोग द्वारा, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के ग्रुप, किसी हस्ती या संघ द्वारा ऐसे रूप में जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, शिकायतों या आरोपों के सम्बन्ध में जो आयोग के समकक्ष की जाएं, जांच की जाएगी।

3. आयोग, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 60) के अधीन रहते हुए, जांच के संचालन के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया अपनाएगा तथा निर्दिष्ट करेगा।

4. जांच आयोग की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें बाद में जारी की जाएंगी।

तथा, चूंकि की जाने वाली जांच के स्वरूप तथा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य की सरकार की भी राय है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2), (3), (4) तथा (5) के उपबन्ध आयोग को लागू करने चाहिए ;

अब, इसलिए, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 60) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निर्देश देते हैं कि उक्त धारा की उपधारा (2), (3), (4) तथा (5) के उपबन्ध आयोग को लागू होंगे।

आयोग यथाशक्यशीघ्र किन्तु इसकी प्रथम बैठक की तिथि से छह मास से अधिक न हो अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

डी० एस० ढेसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Notification

The 14th May, 2015

No. 44/1/2015-5Pol.— Whereas, serious issues concerning public importance relating to the grant of license(s) for developing commercial colonies by the Department of Town and Country Planning, Government of Haryana, to some entities in sector 83, Gurgaon and alleged illegalities therein have come to the notice of the Government of Haryana;

And whereas, the State Government is of the considered opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into this definite matter of public importance, viz. the issues concerning the grant of license for developing commercial colonies by the Department of Town and Country Planning, Government of Haryana, to some entities in sector 83, Gurgaon and their subsequent transfer/disposal, allegations of private enrichment, ineligibility of the beneficiaries under the rules and/or other matters incidental thereto or connected therewith;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (Central Act 60 of 1952), the Governor of Haryana appoints Mr. Justice S. N. Dhingra (Retd.) of the Hon'ble High Court of Delhi as the Commission of Inquiry with the following terms of reference,-

1. The Commission shall make an inquiry and give its findings and recommendations with respect to the following matters, namely:-

   (a) the circumstances under which license(s) for development of commercial colonies were granted to some entities in sector 83, Gurgaon;

   (b) whether the said entities were eligible for grant of license(s) as per the applicable laws, rules, circulars, notifications, guidelines etc. prevalent in the State of Haryana including in the Department of Town and Country Planning, Haryana;

   (c) whether the transfer of licenses by the original licencee within a short period of time to other entities was violative of law, rules, circulars, notifications and/or guidelines etc.; and whether the Town and Country Planning Department had contemplated the transactions that had taken place before or after the grant of license, particularly with reference to the loss of revenue to Government;

   (d) to recommend measure(s) which may be adopted to meet the ends of justice, particularly with a view to take corrective action to prevent loss of revenue to the public exchequer and also prevention of undue private enrichment at the cost of the public exchequer in such cases in the future;

   (e) to consider such other matters, including, complaints given by different individuals, magazines, political parties and also the Comptroller and Auditor General reports etc. on the subject;

   (f) to give findings and recommendations to meet the ends of justice, particularly relating to allegations of criminal conspiracy, criminal misconduct and undue private enrichment, if any and the role of public servants and private individuals therein; and

   (g) to recommend remedial measures for systemic improvement, with a view to prevent loss of revenue to the public exchequer and undue private enrichment in future.

2. The inquiry by the Commission shall be in regard to complaints or allegations that may be made before the Commission by any individual, group of individuals, entity or association in such form, as may be specified by the Commission.

3. The Commission shall devise and specify its own procedure for conduct of the Inquiry subject to provisions of the Commissions of Inquiry Act, 1952(Central Act 60 of 1952).

4. The terms and conditions of appointment of the Commission of Inquiry shall be issued later on.

And, whereas the Government of Haryana is also of the opinion that having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) of section 5 of the said Act should be made applicable to the Commission;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (Central Act 60 of 1952), the Governor of Haryana hereby directs that the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) of the said section shall apply to the Commission.

The Commission shall submit its report to the State Government as soon as possible but not later than six months from the date of its first sitting.

D. S. DHESI,
Chief Secretary to Government of Haryana.

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

ORDER

The 14th May, 2015

No. ECA-7-2015/31934.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of Rule 6 of the Haryana Panchayati Raj Election Rules, 1994, I, Chander Shekhar, IAS, Director, Development and Panchayats, Haryana, Chandigarh reserve the offices of the Presidents of the following Zila Parishads for women, detailed as below, by rotation and by draw of lots held on 13th May, 2015 at 11:00 A.M. for which statutory notice under Sub-rule (2) of Rule 6 of the Haryana Panchayati Raj Election Rules, 1994 was issued on 5th May, 2015:—

Sr. No.	Name of Zila Parishads	Reserved for
1.	Sonipat	Scheduled Caste Woman
2.	Rewari	Scheduled Caste Woman
3.	Jind	Woman
4.	Karnal	Woman
5.	Kaithal	Woman
6.	Panchkula	Woman
7.	Sirsa	Woman

CHANDER SHEKHAR,
Director, Development and Panchayats Department,
Haryana, Chandigarh.

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

ORDER

The 14th May, 2015

No. DPH-LA/ZP-2015/569.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of Rule 6 of the Haryana Panchayati Raj Election Rules, 1994, I, Chander Shekhar, IAS, Director, Development & Panchayats Department, Haryana, Chandigarh hereby reserve the offices of Presidents of Zila Parishads, Sonipat, Rewari, Palwal and Panipat for the persons belonging to Scheduled Castes on the basis of the largest maximum percentage population of Scheduled Castes as per 2011 census in the district of Sonipat, Rewari, Palwal and Panipat.

CHANDER SHEKHAR,
Director, Development and Panchayats Department,
Haryana, Chandigarh.

53345—C.S.—H.G.P., Chd.